

दैनिक रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक




Page - 4

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

→ 11 या 12 दिसंबर तक हो सकता है महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार...

बीजेपी
को मिल सकते
है 20 से ज्यादा
मंत्री पद



मुंबई : देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार का मर्गिमंडल विस्तार 11 या 12 दिसंबर को होने की संभावना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पूरी संभावना है कि अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP वित्त विभाग और भाजपा गृह विभाग अपने पास रखेंगी, जैसा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में था। शिवसेना सूत्रों की माने तो शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना शहरी विकास मंत्रालय अपने पास रखेंगी और राजस्व मंत्रालय भी उसे मिल सकता है।

इससे पहले नई सरकार में गृह विभाग

अपने पास रखने को लेकर शिंदे की नाराजगी की खबरें पिछले कई दिनों से मीडिया में छाई हुई थीं। उनके कर्तीवियों के मुताबिक वे उपमुख्यमंत्री बनने को भी तैयार नहीं थे लेकिन बहुत मनाने के बाद आखिरकार वे मान गए और कल मुंबई में हुए शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने डासीएम पद की शपथ ली।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं। महायुति

गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 21-22 मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार शिवसेना को 11 से 12 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को 9 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं।

मंत्रियों की संख्या का जल्द

होगा खुलासा

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या पर अंतिम फैसला एक से दिन में ले लिया

जाएगा। नवनिर्वाचित विधायकों को शनिवार से शुरू हो रहे विधानसभा के तीन दिवसीय विशेष सत्र में प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलांबकर शपथ दिलाएंगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 9 दिसंबर यानी सोमवार को होगा, जिसके बाद नयी सरकार का विश्वास मत होगा और राज्यपाल दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से राज्य की दूसरी राजधानी नागपुर में शुरू होगा।

इससे पहले बीते रोज गुरुवार को मुंबई के आजाद मैदान में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के नए सीएम के तौर पर शपथ ली। इसके अलावा अंतीत पवार और एकनाथ शिंदे ने उपमुख्यमंत्री की शपथ ली। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता और कारोबार, फिल्म व खेल जगत की कई मशहूर हस्तियां मौजूद रहीं।

महाराष्ट्र / पूर्व मंत्री मधुकर पिंडका निधन... 84 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस



महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे मधुकर पिंडका का शुक्रवार को नासिक के एक अस्पताल में बीमारी के चलते निधन हो गया। उन्होंने 84 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। एनसीपी नेता और उनके साथी रहे छान भुजबल ने बताया कि पिंडका को पिछले महीने ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें संक्रमण हो गया और पांच-छह दिन पहले उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया था। पूर्व मंत्री मधुकर पिंडका 1980 से 2009 तक अहिल्यानगर जिले के अकोले विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आदिवासी समुदाय के एक प्रमुख नेता थे। वे कई सरकारों में मंत्री रहे। शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद वह विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। 1999 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए।

72 वर्षीय महिला के घर में घुसकर किया प्रताड़ित, फिर लूट को दिया अंजाम...

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार



मुंबई: मीरोड पूर्व के नयानगर पुलिस थाने की सीमा में एक बेहद चौंकाने वाली घटना घटित हुई है। जिसमें एक चोर ने खुद को इलेक्ट्रीशियन बताकर 72 वर्षीय महिला के घर में घुस कर करीब 8 घंटे तक उसकी पिटाई कर प्रताड़ित किया। इसके बाद महिला के 30-35 ग्राम वजन के कंगन छीन कर फरार हो गया। इस मामले में नयानगर पुलिस थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले की

के पास से आरोपी मो.सलीम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नयानगर का ही रहने वाला है।

संवेदनशीलता को देखते हुए क्राइम ब्रांच (यूनिट-1) के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अविराज कुराडे ने मामले की जांच शुरू कर दी। उनकी टीम वांछित अज्ञात आरोपी की तलाश में जुट गई, नीतीजन घटना स्थल से मिले सबूतों और पुख्ता जानकारी के आधार पर शुक्रवार को नया नगर पुलिस थाने और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने मीरा रोड स्टेशन

महाराष्ट्र में किसान परिवारों का बुरा हाल... मराठवाड़ा क्षेत्र में इस साल 822 किसानों ने की आत्महत्या!

छत्रपति संभाजीनगर:

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के आठ जिलों में 2024 में अब तक 800 से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर लिया है। जिनमें से 303 मामलों में मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि 314 ऐसे मामले हैं, जिनका जांच लंबित है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष मामलों में से 303 मामलों में 30



जनवरी से अब तक मराठवाड़ा में 822 किसानों ने आत्महत्या की है, जिसमें बीड़ में सबसे अधिक 160 किसानों ने आत्महत्या की। रिपोर्ट में कहा गया है कि 822 मामलों में से 303 मामलों में 30

नवंबर तक कुल 3.03 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। वहीं, 314 मामलों में जांच लंबित है। रिपोर्ट के अनुसार, बीड़ के बाद मराठवाड़ा के नादेड (146) में सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्या की। उसके बाद धाराशिव (143), छत्रपति संभाजीनगर (132), जालना (76), लातूर (72), परभणी (64) और हिंगोली (29) किसानों ने आत्महत्या की।

संपादकीय...



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में अपने एक आदेश में सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से कहा है कि वे अपने यहां यौन-प्रताड़ना निरोधक कानूनों का क्रियान्वयन करें। इससे पता चलता है कि हमारे यहां कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने में कितनी कम रुचि ली जाती है। यह बात इसलिए भी परेशान करने वाली है कि ये आदेश संसद द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम यानी पॉश अधिनियम के 2013 में पारित होने के 10 साल से अधिक समय के बाद आया है। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गत वर्ष मई में दिए गए उस बयान के बाद आया है जिसमें गोवा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर द्वारा छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों के विरुद्ध अपील के मामले में उसने कहा था कि अधिनियम के क्रियान्वयन में गंभीर चूक हुई है। उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तृत निर्देश जारी किए थे और केंद्र, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों से कहा कि वे इस बात की पुष्टि करें कि क्या उनके अधीन आने वाले सभी विभागों ने जिलों में स्थानीय शिकायत समिति या आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है, क्या उनके बारे में सूचनाओं का समुचित प्रसार किया गया है, और क्या नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? अपने इस आदेश में न्यायालय ने इन समितियों के गठन के लिए जनवरी 2025 की समय सीमा तय की है।

महिलाओं द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए शीबॉक्स पोर्टल्स बनाने की बात कहने के साथ ही न्यायालय ने कहा कि यह सब मार्च 2025 के पहले हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी अदालत से बार-बार ऐसी घोषणा का आना यह रेखांकित करता है कि देश में महिलाओं के संरक्षण के लिए कितनी धीमी गति से काम किया जा रहा है। इसमें आश्वर्य की कोई बात नहीं है। गत वर्ष महिला पहलवानों ने अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख पर यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्रदर्शन किया था और उसके पश्चात हुई जांच में पाया गया कि देश की अधिकांश अधिमान्य खेल संस्थाओं में आंतरिक शिकायत समितियां नहीं हैं। इस वर्ष के आरंभ में कोलकाता के आरजी कर मैडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षण महिला चिकित्सक के बलात्कार और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार ने अस्पष्ट प्रतिक्रिया दी थी जिससे कार्य स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उदासीनता का भाव उजागर हुआ था।



editor@rokthoklekhaninews.com



+91 8657861004



Faisal Shaikh @faisalrokthok



youtube@rokthoklekhaninews.com

LIKE

SHARE

COMMENT

SUBSCRIBE

समाचार

2



ईडी ने मनी लॉन्डिंग जांच के तहत 16.42 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया...

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 458.24 करोड़ रुपये के संदिग्ध बिक्री बिल बनाने और 28.34 करोड़ रुपये के मूल्य वर्धित कर (वैट) का भुगतान न करने में कथित रूप से शामिल फर्जी संस्थाओं के एक समूह से संबंधित मनी लॉन्डिंग जांच के तहत 16.42 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कई आरोपी व्यक्तियों की चल-अचल संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया।

एजेंसी ने त्रिशूल एंटरप्राइजेज सहित कुछ फर्जी संस्थाओं के खिलाफ सांगली पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज मामले के आधार पर अपनी जांच शुरू की। आरोप है कि ये फर्जी संस्थाएं महाराष्ट्र भर में अलग-अलग संस्थाओं को 458.24 करोड़ रुपये के फर्जी बिक्री बिल



जारी करने में शामिल थीं और उन्होंने 28.34 करोड़ रुपये का वैट नहीं चुकाया था, जिससे धारा 420 और महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत अपराध हुआ।

आईएसबी के व्यापक प्रमाणन कार्यक्रम के साथ अपने आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करियर को बदलें आज ही जुड़ें ईडी की जांच से पता चला है कि 17 संदिग्ध संस्थाओं का उपयोग करके कथित तौर पर 919 करोड़ रुपये के फर्जी चालान बनाए गए थे, जबकि कभी भी एक भी वास्तविक बिक्री या खरीद नहीं की गई।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, 'इस तरह से अर्जित कमीशन मामले की अपराध आय है, जो नकली बिक्री बिल जारी करने के अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई थी।' ईडी ने इससे पहले जून 2023 में प्रमुख आरोपियों के आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था।

पुणे : 23 वर्षीय आर्म रेसलर काइल कमिंग्स को जमानत... इंग्स मंगवाने का आरोप



मुंबई : मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे के 23 वर्षीय आर्म रेसलर काइल कमिंग्स को जमानत दे दी, जिस पर बेलियम से प्रतिबंधित इंग्स मंगवाने का आरोप है। अंतर्राष्ट्रीय आर्म-रेसलिंग प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके कमिंग्स को मई 2024 में दो अन्य लोगों के साथ मेथमफेटामाइन और एमडीएमए खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसे आमतौर पर एक्सट्रीम के रूप में जाना जाता है।

यह मामला कस्टम्स की विशेष जांच और खुफिया शाखा द्वारा शुरू किया गया था, जिसने सह-आरोपी श्रवण जोशी के बारे में विशेष खुफिया जानकारी के बाद एक संदिग्ध पार्सल को रोका था। जांच करने पर, पार्सल में 230 ग्राम MDMA और 51 ग्राम मेथमफेटामाइन पाया गया। अधिकारियों ने एक डमी पार्सल का उपयोग करके एक नियंत्रित डिलीवरी ऑपरेशन स्थापित किया, जिसके कारण जोशी की गिरफ्तारी हुई जब

मुंबई दो भूखंड आइवरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट ने ₹355 करोड़ में खरीदा...



मुंबई : मुंबई दो भूखंड, जिनमें से एक बेसाइड मॉल है, दक्षिण मुंबई के ताइदेव में शहर के पहले मॉल, क्रॉसरोड्स के सामने लोकप्रिय खुदरा स्थान है, को आइवरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट ने ₹355 करोड़ में खरीदा है। डेवलपर के रहेजा कॉर्प से जुड़ा आइवरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट, कंपनियों में शेररहोल्डिंग खरीदने के साथ-साथ रियल एस्टेट की खरीद और बिक्री में शामिल है।

आईएसबी के व्यापक प्रमाणन कार्यक्रम के साथ अपने आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करियर को बदलें आज ही जुड़ें रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म सीआरई मैट्रिक्स के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, आइवरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट ने एए होलिडंग ट्रस्ट से 1,216.29 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले बेसाइड मॉल और 1,070.24 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले पॉपुलर प्रेस बिल्डिंग को खरीदा है। संयुक्त क्षेत्रफल 2,286.53 वर्ग मीटर (या 24,612 वर्ग फीट) है।



वरिष्ठ नागरिक से 3.81 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में तीन लोग गिरफ्तार

मुंबई : मुंबई शहर की साइबर पुलिस ने 3-4 दिसंबर को शेयर बाजार में निवेश में उच्च रिटर्न का लालच देकर एक वरिष्ठ नागरिक से 3.81 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक सतीश यादव ने एक फर्जी कंपनी खोली थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने अपने बैंक खाते से 1.50 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। यादव दिवा के बीआर नगर में रहता है, जबकि अन्य दो आरोपी विकास मौर्य और

सचिन चौरसिया क्रमशः मुंब्रा और दिवा ईस्ट में रहते हैं।

आईएसबी के व्यापक प्रमाणन कार्यक्रम के साथ अपने आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करियर को बदलें आज ही जुड़ें पुलिस के अनुसार, 76 वर्षीय शिकायतकर्ता बीच कैंडी इलाके में रहता है और ऑटोमोबाइल पार्ट्स का निर्यात करता है। उन्होंने दिवा किया कि उन्हें शेयर बाजार में निवेश के बारे में उनके व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला। उन्होंने सदैश में दिए गए नंबर पर संपर्क किया और जल्द



ही उन्हें स्टॉक प्लान मिलने लगे। शुरूआत में, शिकायतकर्ता ने छोटी राशि का निवेश किया और देखा कि उन्हें भारी रिटर्न मिल रहा

है। इसके बाद, उसने 14 फरवरी से 28 मार्च के बीच 28 ट्रांजैक्शन किए, जिसमें 3.81 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।

जब शिकायतकर्ता ने अपने शेयर बेचने की कोशिश की, तो ब्रोकर ने उसके कॉल का जवाब देना बंद कर दिया। जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उसने सेंट्रल साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। जांच के बाद, पुलिस ने मई में एक एफआईआर दर्ज की। सेंट्रल साइबर पुलिस स्टेशन की पुलिस इंस्पेक्टर मौसमी पाटिल ने कहा, “जांच के दौरान, यह पाया गया कि ठगी की गई राशि में से 1.50 करोड़ रुपये शील्ड एसेसिएट नामक शेल कंपनी के खाते में जमा किए गए थे, जिसे सतीश यादव ने स्थापित किया था। आरोपियों ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक खाता खोला था।” आरोपियों को आईपीसी की धारा 419, 420, 465, 467, 468, 471, 34 और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 4-5 दिसंबर में पेश किया गया, जिसने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया।

रोजाना निकल रहा है 6200 मीट्रिक टन कचरा

मनपा का दावा, मुंबई में कम हुआ कचरा निकलने का प्रमाण

मुंबई : मनपा प्रशासन ने दावा किया है कि मुंबई से रोजाना निकलने वाले कचरे के प्रमाण में कमी आई है। मुंबई में मानसून के दौरान रोजाना 6850 मीट्रिक टन कचरा निकलता था। जिसमें अब गिरावट हुई है अब रोजाना 6200 मीट्रिक टन हुआ है।

कचरा का प्रमाण कम होने को लेकर मनपा के पास कोई विशेष उपाय सामने नहीं आया है। मनपा के कचरा विभाग के अधिकारियों



का कहना है कि मुंबई से रोजाना निकलने वाले कचरे के प्रमाण में कमी आई है। मनपा प्रशासन ने कचरे का प्रमाण कम होने को लेकर लोगों में कचरे के निपटान करने में आई जन जागरूकता बताया जा रहा है। लेकिन यह

कितना सही और जमीनी हकीकत है यह आने वाला समय बताएगा। कचरा रखने के लिए बने डम्पिंग ग्राउंड में देवनार डम्पिंग ग्राउंड की पहले क्षमता खत्म हुई है। कांजुर डम्पिंग ग्राउंड पर कचरे की पर्सेसिंग होने के कारण कुछ हद तक पाई है।

घटना में ट्रक

ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं दो अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस जगह पर एमएमआरडॉए ने ठेकेदार जय कुमार कम्पनी के द्वारा मेट्रो का काम करा रही है, जहां यह हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद मैके पर पहुंचे शिवसेना के राम भुवन शर्मा ने बताया कि जिस जगह पर यह गड़ा खोदा गया था। वहां पर ठेकेदार के द्वारा किसी भी प्रकार के सुरक्षा उपाय नहीं किया गया था। इसी एक गलती के कारण यह हादसा हुआ और ट्रक चालक की मौत हुई है।

मीरारोड : सीमेंट रेडी मिक्स दुर्घटनाग्रस्त...

हादसे में ट्रक चालक की मौत !



मीरारोड : मीरा भायंदर शहर में मेट्रो का काम चालू है। इस काम के बजह से यहां आये दिन हादसे होते रहते हैं, जिसके कारण कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। बुधवार देर रात को काशीमिरा स्थित अमर पैलेस हॉटेल के सामने सीमेंट रेडी मिक्स के ट्रक ड्राइवर

की दुर्घटना में मौत हो गयी, वहीं दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना स्थल पर मेट्रो का काम करने वाले ठेकेदार के द्वारा गड़ा खोद कर पानी का टैंक बनाया जा रहा था। उस जगह पर सीमेंट की भराई करते वक्त ट्रक असंतुलित होकर उस गड़े में पिर गया, इस

पश्चिम रेलवे पर बे टिकट यात्रियों को करनी पड़ी जेब ढीली ...

जुमार्ने के तौर पर वसूले गये 93.47 करोड़ रुपये



मुंबई : पश्चिम रेलवे पर सभी वैध यात्रियों को आरामदायक यात्रा और बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेनों, मेल/एक्सप्रेस के साथ- साथ पैसेंजर ट्रेनों और हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों में बिना टिकट / अनियमित यात्रियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार गहन टिकट जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारियों की निगरानी में अत्यधिक अनुभवी टिकट जांच टीम द्वारा अप्रैल से नवंबर के बीच कई टिकट जांच अभियान चलाए गए, जिनसे 93.47 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए। इस राशि में मुंबई उपनगरीय खंड से प्राप्त 30.63 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी विनीत अधिकारी के द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नवंबर के

